



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३५]

शुक्रवार, नोव्हेंबर ६, २०१५/कार्तिक १५, शके १९३७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ६०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३० अक्टूबर २०१५ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XX OF 2015.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA UNIVERSITIES ACT, 1994.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २०, सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ में अधिकतर संशोधन करने का महा. ३५। के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

(१)

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

सन् १९९४ का
महा. ३५ की
धारा ८२ का
संशोधन।

२. महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ की धारा ८२ की, उप-धारा (३) में, निम्नलिखित परंतुक, सन् १९९४ का महा. ३५।
जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“ परंतु, सन् २०१६-२०१७ के अकादमिक वर्ष से उच्चतर अध्यापन के नए महाविद्यालय या संस्था शुरू करने की अनुमति लेने के लिए प्रबंधमंडल, ३१ दिसंबर २०१५ को या के पूर्व विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करेगा ।” ।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (सन् १९९४ का महा. ३५) की धारा ८२ उच्चतर अध्यापन के नए महाविद्यालय या संस्था शुरू करने की अनुमति के लिये प्रक्रिया का उपबंध करती है। उक्त धारा ८२ की उप-धारा (१) यह उपबंध करती है कि, विश्वविद्यालय, एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाएगी और विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर, विशिष्टतया, अपर्याप्त और अल्पविकसित क्षेत्रों की जरूरतों को सम्यक्तया ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षा के लिए सुविधाओं का समान वितरण सुनिश्चित करने की रीति में शैक्षणिक विकास के लिए उच्चतर विद्या के महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के स्थान निर्धारण के लिए उच्च शिक्षा राज्य परिषद द्वारा उसका अनुमोदन लेगी। उक्त धारा ८२ की, उप-धारा (२) यह उपबंध करती है कि, उच्चतर अध्यापन के नए महाविद्यालय या संस्था को शुरू करने के लिए कोई भी आवेदन जो कि ऐसी योजना के अनुरूप नहीं है तो, वह विश्वविद्यालय द्वारा उसका विचार नहीं करेगा। उक्त धारा ८२ की, उप-धारा (३) यह उपबंध करती है कि, उच्चतर अध्यापन के नए महाविद्यालय या संस्था को शुरू करने के लिए अनुमति चाहनेवाले प्रबंधन, जिस वर्ष से अनुमति लेना चाहते हैं उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के अक्टूबर के अंतिम दिनांक के पूर्व विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को विहित प्रारूप में आवेदन करेंगे।

२. सरकार ने, विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे परिप्रेक्ष्य योजना बनाते समय उस पर विचार किया जाए। ऐसे साधारण मानकों का अध्ययन करने के लिए डा. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता के अधीन एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को १४ अक्टूबर २०१५ को महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की ली गई बैठक में सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी अकृषिक विश्वविद्यालय उक्त समिति की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार परिप्रेक्ष्य योजना बनाएंगे। उक्त धारा ८२ की उप-धारा (२) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय, ऐसी परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, उच्चतर अध्यापन के नए महाविद्यालय या संस्था को शुरू करने के लिए आवेदन का विचार करेंगे। इसलिए, धारा ८२ की उप-धारा (३) के अधीन, अकादमिक वर्ष २०१६-२०१७ से उच्चतर अध्यापन के नए महाविद्यालय या संस्था को स्थापित करने के लिए प्रस्तावों की प्रस्तुतिकरण के दिनांक को ३१ दिसंबर २०१५ तक बढ़ाना इष्टकर समझा गया था।

३. विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपरोल्लिखित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ (सन् १९९४ का महा. ३५) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुम्बई,
दिनांकित : ३० अक्टूबर २०१५।

चि. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

संजय चहांदे,
शासन के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।